

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

4-9-17 पत्रावली पेश हुई। बन्दी वादी हाजिर। संशोधित चर्चले पेश करने हेतु दिनांक 10-10-17 को पेश की।
 10-10-17 पत्रावली पेश हुई। बन्दी वादी हाजिर। संशोधित चर्चले पेश करने हेतु दिनांक 28-11-17 को पेश की।
 28-11-17 पत्रावली पेश हुई। बन्दी वादी हाजिर। संशोधित चर्चले पेश करने हेतु दिनांक 28-1-17 को पेश की।
 30-1-18 दिनांक 28-1-18 को केसफर कोष में पत्रावली पेश की गई। 20 साख बाहर प्रचारों में दिनांक 28-2-18 को पेश की।
 28-2-18 पत्रावली पेश हुई। बन्दी वादी हाजिर। संशोधित चर्चले पेश करने हेतु दिनांक 17-4-18 को पेश की।

17-4-18 पत्रावली पेश हुई। न्याय आण्ड
 हार अमियान 2018 को तहत राजस्व केस में राजीनामा
 हेतु दिनांक 6-6-18 प्रापं पत्रावली
 को पेश हो।

06-06-18 पत्रावली पेश हुई। 1. प्रार्थी वादी कल्याण, बन्दी, मुनी हाजिर सुना गया संसद में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सापुण्डा की जमाबंदी संवंत अ.क्रि. नं. 204 के खता सं. नया-पुराना 265-250 खसरा नं. 765/439 रकबा 25-03-00 बाराही 3 के पुराने खसरे नं. 439/1 रकबा 67 बिघा 01 बिस्का गैर युमदिन ड्रापर पर जो प्रामाणिक दस्तावेजों में सुगन कवर पत्नी कं. श्री रामल सिंह की खातेदारी की जरूरत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04-09-76 को प्रार्थी सं. 1 बन्दी व प्रार्थी संख्या 2 के लगायत 4 के पत्र व पिता • बिरवा पुत्र श्री हरलाल जाति गुर्जर. नि. सापुण्डा त. सरवाड नं 2500 रु. में खुरिद लि थी। ये विक्रय पत्र सब रजिस्ट्रार सरवाड के कार्यालय में दिनांक 16-09-76 को पुस्तक सं. 1 डि

के डिप्लोमी
 अ.क्रि. नं. 204

- जिल्द सं. 32 पृष्ठ सं 15, 16 क.स. 28। प्रार्थी सं।
बन्नी व बिरदा पिसरान हरलाल गुर्जर के हक में पंजीबद्ध
किया गया।

बिरदा पुत्र हरलाल गुर्जर केरा व श्रीमती छुकरानी जी
साहब सुगन कुंवर जी का स्वर्गवास हो गया है। किन्तु
उक्त रजिस्टर्ड विद्रुप पत्र के आधार पर केरा के नाम
इन्दाज नहीं किया गया। सुगन कुंवर जी के वारिसाने

अप्रार्थी सं. 1 से 8 के नाम दर्ज कर दिया जो
जल्द है। अतः वादीगण ने वादपत्र अपने पक्ष में
नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु पेश किया है।

अतः वादी का वाद खातेदारी घोषणा बाकत 88, 89
92A, 188, 209 RTA के तहत पेश किया गया है।

वस्तुतः यह वाद प्राथम पत्र में वर्णित आराजी का
विद्रुप फ्रैगमेंट में होने से नामान्तकरण खुलना
नहीं पाया जाता है। अतः तहसीलदार सरवाड़
मौके की जांच करें तथा कब्जा तथा विद्रुप पत्र
के अनुसरण में नामान्तकरण की कार्यवाही करें।
फ्रैगमेंट के नियम के तहत नामान्तकरण के प्रावधान
राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में हट। विल गए हैं।

1 खर्चा फरिक्तेन अपना-अपना वहन करें।

निर्णय प्रसंग में सामने सुनाया गया।

सदस्य

लोक अदालत शिबिर
सरवाड़ (अजमेर)

अध्यक्ष

लोक अदालत शिबिर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिबिर
सरवाड़ (अजमेर)